

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 12225  
दिनांक 12.03.2025 को उत्तर देने के लिए

खनिज की खोज के संबंध में भारत का श्रीलंका के साथ सहयोग

12225. श्री बसवराज बोम्मई:  
श्री बिभु प्रसाद तराई:  
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क :

(क) क्या भारत खनिज की खोज और खनन के संबंध में श्रीलंका के साथ सहयोग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इससे भारत को होने वाले व शष्ट लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समझौता ज्ञापन के प्रमुख उपबंध क्या हैं और इससे खनिज अन्वेषण में द्वपक्षीय सहयोग कस प्रकार सुकर होगा;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कन-कन उपायों पर वचार क्या जा रहा है क इस भागीदारी के अंतर्गत खनिज अन्वेषण और खनन संबंधी गति व धयां पर्यावरण की ष्टि से संधारणीय हों;

(ङ) क्या सरकार दोनों देशों में खनन और खनिज प्रसंस्करण में सुधार लाने के लिए संयुक्त अनुसंधान और प्रौद्योगिकी-भागीदारी पहलों पर वचार कर रहीं है;और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री  
(श्री जी. कशन रेड्डी)

(क) से (ग): जी, हां। श्रीलंका ग्रेफाइट, इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकोन और फॉस्फेट जैसे औद्योगिक खनिजों, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के रूप में चहिनत खनिजों में से हैं, से समृद्ध है। ये खनिज सौर पैनल, पवन चक्कियों, बैटरी और वद्युत वाहनों जो स्वच्छ

ऊर्जा और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन के लिए अभिन्न अंग हैं, जैसी हरित प्रौद्योगिकियों में उनके उपयोग के लिए आवश्यक हैं।

श्रीलंका के अप्रयुक्त खनिज भंडार के साथ, भारत घरेलू उद्योग के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की अपनी संसाधन उपलब्धता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित होता है। इस लिए, खान मंत्रालय गवेषण, खनन और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए श्रीलंका सरकार के साथ सक्रय रूप से बातचीत कर रहा है।

(घ): राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 सभी खनन निर्णयों में पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक विचारों को एकीकृत करके सतत खनन को प्राथमिकता देती है। यह प्रदूषण और कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए वैज्ञानिक मानदंडों और वनीकरण विधियों का उपयोग करके पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने पर केंद्रित है। इस नीति में पर्यावरण अनुकूल विधियों के लिए प्रोत्साहन भी शामिल है तथा यह सुनिश्चित करते हुए कि खनन कार्य उत्तरदायी और सतत दोनों हैं, श्रमकों के लिये पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान है।

यह वह मानक है जिसके आधार पर घरेलू स्तर पर या विदेश में सभी खनन कार्यों का सतत विकास ढांचे पर उनके तुलनात्मक कार्य-निष्पादन के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाना है तथा पर्यावरणीय और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सतत विकास विधियों को अपनाने के लिए खनन कंपनियों की ओर से प्रतिबद्धता को लागू करना है।

(ड.) और (च): प्रस्तावित समझौता ज्ञापन में दोनों देशों में खनन और खनिज प्रसंस्करण में सुधार के लिए संयुक्त अनुसंधान और प्रौद्योगिकी साझा करने की पहल को सुविधाजनक बनाने का प्रावधान है।

\*\*\*\*\*